झूठी संसदीय चुनावों का बहिष्कार करें!

एक सच्ची भारतीय जनता की संघीय जनतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करें!

हमारी प्रस्तावित सच्ची वैकल्पिक नवजनवादी क्रांतिकारी कार्यक्रम की एक झलक!

प्रिय जनता और मित्रों!

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया की स्थिति ऐसी न रही कि साम्राज्यवादी देश उपनिवेशों में स्वतंत्र/मुक्ति संघर्षों के वजह से प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन चला सकें। तब दुनिया में औपनिवेशिक शोषण व उत्पीड़न के जगह नव औपनिवेशिक शोषण व उत्पीड़न का दौर शुरू हुआ। 1947 में हमारे देश भारत में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन खत्म हुआ। देश को औपचारिक (नकली) आजादी मिली पर एक बहुत बड़ी कीमत पर। धर्म के नाम पर, अंग्रेजों के षडयंत्र के परिणामस्वरूप व उनके साथ देशी दलाल शासकों की मिलीभगत से, अभूतपूर्व खून-खराबे के बाद ही देश का विभाजन हुआ। भारत के बड़ा पूंजीपतियों व जमीन्दारियों ने पूरे औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के दलाल मददगार व विश्वस्त सेवक बने रहे व अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीय जनता का शोषण करते हुए ही, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ जारी स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व प्रदान कर जनता को धोखा देते रहे। इन्हीं दलाल पूंजीपतियों व जमीन्दारों के हाथों सत्ता का हस्तांतरण हुआ। ब्रिटिश वाले चले जाने के साथ-साथ देश में साम्राज्यवादियों की लूट व परदे के पीछे से राजनीतिक नियंत्रण बेरोकटोक जारी रखने की नीति की अमल शुरू हुई। इस तरह औपनिवेशिक और अर्धसामंती भारत एक अर्द्ध-औपनिवेशिक व अर्द्ध-सामंती देश में तब्दील हो गया। इसलिए इस लुटेरी व्यवस्था व साम्राज्यवादियों के हितों

को संरक्षण देते हुए जनता पर लगातार शोषण व उत्पीड़न जारी रखने के लिए पहले इन शासक वर्गों की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस सत्ता में आई।

बड़े पूंजीपति व सामन्तों की इस सरकार ने देश के विकास के नाम पर ऐसी नीति अपनायी जिससे साम्राज्यवादी (विदेशी) पूंजी व तकनीक पर देश की निर्भरता बढ़ती गयी। प्रशासन, राजनीति, न्यायपालिका, सेना, आर्थिक नीति, शिक्षा, संस्कृति आदि में औपनिवेशिक ढांचा में ही बहुत हद तक अक्षुण्ण बने रहे, सच्ची/स्वतंत्र बुनियाद पर निर्माण नहीं होने की वजह से उसका कोई जनवादीकरण नहीं हुआ। संसद, जिसे भारतीय जनता के प्रतिनिधियों की सभा कहा गया, दरअसल उत्तर–47 विश्व के सबसे बड़े झूठों में से एक है। संसद में लिये गये फैसले बड़े उद्योगपतियों, बड़े जमींदारों व उनके तरफदार कुछ कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा लिये गये फैसले होते हैं। संसद में किसी बिल के पास होने न होने का फैसला साम्राज्यवादियों व लुटेरी वर्गों के हितों के समर्थन में संसद के बाहर पैसा व ताकत के खेल से तय होता है।

नेहरू के नेतृत्व में बनी सरकार ने पूंजीपतियों द्वारा बनाये गये 'बाम्बे प्लान' को अपनाते हुए पहले पंचवर्षीय योजना की शुरूआत की। तब मंदी व विश्वयुद्ध से टूट चुके अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करने की अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में व सोवियत समाजवादी गणराज्य के प्रभाव व विकास से घबराये साम्राज्यवादियों ने कींस का नुस्खा मान राजकीय (सार्वजनिक/सरकारी) पूंजी की भागीदारी अर्थव्यवस्था में शुरू की व एक 'कल्याणकारी' पूंजीवादी राज्यों का ढोंग सामने लाया। तब भारत की अर्थव्यवस्था भी बुरे हाल में थी। ठहरी हुई बाजार व्यवस्था, औद्योगिक विकास की ढांचागत सुविधाओं व उसके लिए देशीय दलाल पूंजीपतियों के पास पर्याप्त पूंजी के अभाव ने शासकों के सामने राजकीय पूंजी की बड़े पैमाने पर जरूरत को सामने लाया। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम पर निजी व सार्वजनिक क्षेत्र अस्तित्व में आये जो साम्राज्यवादी बाजार, उनकी पूंजी (कर्ज) व तकनीक के उपर आश्रित थे। सरकारी देख रेख में, सरकारी पूंजी के साथ पंचवर्षीय योजनाएं देश में दलाल नौकरशाह पूंजीवाद को मजबूत करती गईं।

'कल्याणकारी राज्य' का दावा करने के बावजूद शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल,

निवास जैसी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं पर खर्च घटते गये। बीते 71 वर्षों से इस साम्राज्यवादपरस्त, देशी शासक वर्ग अनुकूल, जनविरोधी व देशद्रोही नीतियों की वजह से ताजा परिस्थिति ठोस रूप से इस प्रकार है – शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए मोदी सरकार की बजट आवंटन सकल घरेलू उत्पादन में सिर्फ 4.4 प्रतिशत ही है। यह सब–सहारन अफ्रीका, पूर्वी एशिया, लातीन अमेरिका के देशों से तुलना करें तो बहुत कम हैं। इस सरकार बच्चों के लिए पौष्टिक आहार, गर्भवति मां, प्रसूति मां व युवतियों के पोषण और सेहत के लिए पैसों की आवंटन 75 प्रतिशत कम कर दिया है। इसके अलावा, 6 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ आसमान छूती महंगाई, सरकारी आंकड़े के मुताबिक ही 9.5 प्रतिशत तक पहुंचने वाली भयंकर बेरोजगारी, बढ़ती मुद्रास्फीति, विशाल विदेशी कर्ज 37,96,200 लाख करोड़ रूपये, राजस्व–घाटा 3.5 प्रतिशत, चालू खाता घाटा 2.5 प्रतिशत तक बढ़ जाना, रूपये की मूल्य गिरकर 74 रूपये प्रति डालर हो जाना, नोटबंदी, 58,000 करोड़ रूपये के राफेल घोटाला, रोटोमाक कंपनी जैसे मंत्री–नेता–अफसरों के भ्रष्टाचार–घोटाले के साथ–साथ बैकों के एनपीए (Non Performing Assets-बट्टा खाते), एलओयू (Letter of Understanding-पत्र के साथ समझौता), एलओसी (Letter of Credit-पत्र के साथ ऋण), विदेशी समझौते जैसे घोटालों द्वारा अपनी चरम पर पहुंचने वाली व्यवस्थीकृत भ्रष्टाचार, विदेशी बैंकों में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कालेधन जमा होना, भयंकर महिला उत्पीड़न, विस्थापन के कारण लाखों लोगों की लाचार स्थिति, तंगहाली व भुखमरी इत्यादि ने जनता की जीवन स्थिति को और बदतर बना दिया है।

पिछले 71 वर्षों के अनुभव इस देश के 73 प्रतिशत संपत्ति सिर्फ 1 प्रतिशत अमीरों के हाथों में केंद्रकृति हो जाने की बात पुष्टि करता है, इससे देश में मुट्ठीभर अमीर और अमीर हुए हैं और विशाल संख्या में गरीब और गरीब हुए हैं। दरअसल, देश में रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, खाद्यान्न व आवास – इन बुनियादी अधिकारों से 65 करोड़ जनता वंचित है। विश्व में पौष्टिक आहार की अत्यंत कमी होने वाले बच्चे अधिकतर हमारी देश में हैं। देश के 30 करोड़ जनता भूखे हैं, 49 करोड़ लोग गरीबीरेखा से नीचे जी रहे हैं। विगत

यूपीए सरकार की तरह मोदी सरकार एलपीजी नीतियों को लागू करने के कारण मजदूरों व कर्मचारियों के वास्तविक वेतन तेजी से गिर रही है। सरकार आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत होने की ढंढोरा भजाने के बावजूद, गलत आंकड़े दिखाने में माहिर मोदी सरकार ने 2015 से वास्तविक वृद्धि को 2 प्रतिशत बढ़ाकर दिखा रही है। इसलिए मोदी की शासन में रोजगार सिर्फ 1.1 प्रतिशत ही मिली है। हर साल 2 दो करोड़ रोजगार देने की वादा करने वाले मोदी 2016-17 में सिर्फ 4.16 लाख रोजगार ही दे पाये हैं। नोटबंदी के वजह से 3 लाख छोटे और मझोले उद्योग बंद होकर 2 करोड़ नौकरियां चली गयी व जीएसटी के कारण व्यापार में मंदी और बढ़कर 15 करोड़ लोग काम करने वाली सूक्ष्म, छोटे व मझोले उद्योगों को नुकसान हुई है। 'ई वे' बिल के कारण व्यापार और छोटे उद्योगों पर बड़े हमले किया है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी पूंजी को खुली छूट देकर, स्थानीय धंधों को ध्वस्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। बेरोजगार इतना बढ़ी है कि उत्तरप्रदेश में 62 चपरासी नौकरियों के लिए 93,000 अर्जी आयी हैं। इसमें 3,740 अर्जी पी.एच.डी. वालों के हैं। 2019 तक देश में 77 प्रतिशत युवक नौकरियों के लिए बेकार होने की स्थिति पैदा हुई है। इससे छात्र-युवा आत्महत्या कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र तीव्र संकट में फंस जाने के कारण देश में 4,68,48,100 किसान कुद 12.60 लाख करोड़ रूपयों के कर्ज तल दबे हुए हैं। मोदी की शासन में किसानों की आत्महत्या तीन गुणा बढ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट में खुद मोदी सरकार ही हर साल 12 हजार से ज्यादा किसान आत्महत्या करने की बात कही है। प्रति 42 मिनटों में एक किसान कहीं न कहीं आत्महत्या कर रहे हैं। देश में विस्थापन की समस्या गंभीर है। खदान, जंगलों में अभयारण्य जैसे बफर जोन व विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन कब्जा करते हुए करोड़ों लोगों को विस्थापित कर रहे हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हवा, पानी, जमीन, खाद्यान्न सभी प्रदूषित हो रही हैं।

हमारी पार्टी मानती है कि समस्याओं की जड़ इस तथाकथित लोकतंत्र के बुनियाद में है। भारत की जनता ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के जरिए केन्द्र में व राज्यों में कई सरकारों को बदला। पर फायदा क्या हुआ? वर्तमान

तंगहाली व भुखमरी किसी एक सरकार के कारण नहीं बल्कि यह पिछले 71 सालों से शासक वर्गों की विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाई गयी जनविरोधी नीतियों का परिणाम है। इसलिए हमारी पार्टी मौजूदा इस पुरानी व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के लिए नवजनवादी क्रांति का नेतृत्व प्रदान कर रही है।

संसदीय राजनीतिक ढांचे में होने वाली चुनावों से आज की देश के अर्द्ध–उपनिवेशवाद व अर्द्ध–सामंतवाद को बदलना नामुमकिन है; इन चुनावों के जरिए सिर्फ इस व्यवस्था को संरक्षण देने और जारी रखने के लिए सत्ता में आने वाली शासक वर्गों के गुटों/राजनीतिक पार्टियों को बदला जा सकता है। यह सिर्फ मुखौटा बदलने के बराबर है। यानी चुनाव के जरिए केवल शासकों/सरकारों का रंग बदलता है, शोषणकारी शासन का अन्त नहीं होता है। हम दीर्घकालीन लोकयुद्ध के जरिये भारत के शासकों – दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों (बड़े पूंजीपतियों) व जमीन्दारों व उनके आका साम्राज्यवाद की सत्ता को खत्मकर शोषित–उत्पीड़ित जनता यानी मजदूर, किसान, निम्न पूंजीपति (छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, साधारण सरकारी व प्राइवेट कर्मचारी, आदि) व देशीय बुर्जुआ (छोटे, मझोले उद्योगपति व व्यापारी), उत्पीड़ित सामाजिक तबकों और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के संयुक्त मोर्चा की सच्ची स्वतंत्र, जनवादी और प्रगतिशील सरकार बनाना चाहते हैं।

प्रसंगवश हम बता दें कि हम फासीवाद, दुराक्रमण/हस्तक्षेप करने वाली युद्धों, राज्य आतंकवाद, सांप्रदायक आतंकवाद, व्यक्तिगत हिंसावाद को हम सख्त खिलाफ हैं। हम सभी तरह के न्यायपूर्ण युद्धों, क्रांतिकारी युद्धों/बगावतों/संघर्षों को समर्थन करते हैं। हम देश की मुक्ति/नवजनवादी भारत का निर्माण के लिए दीर्घकालीन लोकयुद्ध को जारी रखे हुए हैं। इस क्रांतिकारी युद्ध में हम जन–दिशा व वर्ग–दिशा पर सख्ती से अमल करते हैं व शोषित–पीड़ित जनता को दीर्घकालीन लोकयुद्ध में राजनीतिक रूप से गोलबंद करके ही क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं। पर, देशभर में ऐसी सरकार केवल नव जनवादी क्रान्ति सफल होने के बाद ही बन सकती है। यह नई जनवादी सत्ता शासक वर्गों की आज की सड़ी–गली अर्थव्यवस्था राजनीति व संस्कृति का आधार ही आमूलचूल बदल देगी। इसलिए, विगत 50 वर्षों से हमारी पार्टी के नेतृत्व में

देशभर में लाखों-करोड़ों उत्पीड़ित जनता ने लाखों केन्द्री व राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा जारी दमन अभियानों का साहसिक रूप से मुकाबला करते हुए लड़ रहे हैं। इस संघर्ष में हजारों की तादाद में क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं और जनता अपने जान न्योछावर किए हैं। इसके परिणास्वरूप, देश के कई मजबूत क्रांतिकारी इलाकों में क्रांतिकारी जन कमेटियां (स्थानीय नवजनवादी सरकारें) गठित होकर वैकल्पिक राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्राथमिक रूप से अमल कर रहे हैं। इस तरह की प्रयास को जारी रखने द्वारा ही देश में सच्ची स्वतंत्र, प्रगतिशील, प्रतिभाशाली आत्मनिर्भर, धर्मनिरपेक्ष व जनवादी व्यवस्था को स्थापित की जा सकती है, योजनाबद्ध ढंग से उसे मजबूत किया जा सकता है। ऐसा भारत सचमुच धर्मनिरपेक्ष व विभिन्न राष्ट्रीयताओं का स्वैच्छिक संघ होगा। भारत को ऐसा आमूलचूल परिवर्तित करने के लिए सर्वहारा के अगुवायी में हमारी पार्टी के नेतृत्व में चार जनवादी वर्गों, उत्पीड़ित सामाजिक तबकों और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के मित्रता के बुनियाद पर क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चे की सरकार-नव जनवादी सत्ता विभिन्न क्षेत्रों में जो मौलिक कार्यक्रम उठायेगी उसकी एक संक्षिप्त झलक हम प्रस्तुत कर रहे हैं।

एक नयी राज्ययंत्र और नये संविधान की आवश्यकता

सर्वप्रथम नई सामाजिक व्यवस्था के लिए और उसकी विकास के लिए नयी राज्ययंत्र और नये संविधान का होना जरूरी है। दरअसल वर्तमान राज्ययंत्र और संविधान ही देश के व्यापक जनता पर नयी औपनिवेशिक असीमित शोषण और उत्पीड़न करने में मुख्य साधन है जो न सिर्फ देश के मुट्ठीभर अमीरों को और अमीर बनाता है, बल्कि निर्धन या गरीबों को और गरीब बनाने के सिलसिले को बरकरार रखता है और साथ ही, यही भारतीय समाज के वर्गों और सामाजिक तबकों के बीच लगातार अन्तरविरोधों को भी जारी रखता है। जैसे - खेती में जाति आधारित अर्द्ध-सामंती सम्बंध, उद्योग में दलाल बड़ी पूंजी का प्रभुत्व, केन्द्र व राज्यों के बीच अन्तरविरोध, एक पाखंडपूर्ण संघीय गणराज्य, राष्ट्रीयताओं का उत्पीड़न, जातीय दमन व भेदभाव, साम्प्रदायिक दमन व भेदभाव, महिलाओं के साथ पितृसत्तामूलक आचरण

सहित विभिन्न तरह के दमन व भेदभाव बाल–शोषण व उत्पीड़न आदि। इन तमाम अन्तरविरोधों को मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद की मार्गदर्शन में सही तरीके से हल करते हुए समाजवादी समाज के रूप में सफलतापूर्वक परिवर्तन करने हेतु नवजनवादी सत्ता को स्थापित करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक नयी राज्ययंत्र को गठित करने एक नया संविधान–कानूनों लिखे जाने की आवश्यकता है। नया राज्ययंत्र नयी चुनाव प्रणाली व नये संविधान पर आधारित होगा।

नयी जनवादी राज्ययंत्र–संविधान सर्वहारा के नेतृत्व में मजदूर–किसान की मित्रता के बुनियाद पर खड़े कर मजदूरों, किसानों, शहरी मध्यम वर्ग, देशीय पूंजीपतियों, उत्पीड़ित सामाजिक तबकों और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के जनवादी राज्ययंत्र व संविधान के रूप में होंगी। यह इन चार वर्गों, उत्पीड़ित सामाजिक तबकों और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी विकास व उन्नत परिवर्तन के लिए मुख्य साधन के रूप में होंगी। इसके लिए सर्वप्रथम आज की शोषण व उत्पीड़न के बुनियाद के रूप में रही उत्पादन संबंधों को रद्द कर, नवजनवादी राज्य के लिए बुनियाद के रूप में रहने वाली उत्पादन संबंधों को स्थापित करने के साथ–साथ पुराने उत्पादन संबंधों के बुनियाद पर बने व शोषक वर्गों की सेवा करते हुए उनका प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीति व संस्थानों को रद्द करती है। सामाजिक उत्पीड़न व भेदभाव को रद्द करती है। सांस्कृतिक क्षेत्र में क्रांति को लगातार आगे बढ़ाती है। यह शोषक वर्गों अवशेषों और क्रांति के जरिए उखाड़े गए शोषक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्तियों को नियंत्रित करते हुए व उनको शिक्षा दिलाते हुए परिवर्तन कराने के लिए उनपर, साम्राज्यवादी दलालों पर, प्रतिक्रांतिकारी तत्वों व देशद्रोहियों पर नवजनवादी अधिनयकत्व को अमल करती है। व्यापक जनता और देश की बहुमुखी विकास के लिए देश की स्वतंत्रता व सम्प्रभुता को संरक्षित करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैनिक, सांस्कृति, पर्यावरण आदि सभी कार्यक्रमों में और राज्य व्यवहारों में भी जनता की चेतनापूर्वक व सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने की प्रयास करती है। देश के विभिन्न उत्पीड़ित वर्गों, सामाजिक तबकों और

राष्ट्रीयताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद अंतरों को हटाते हुए मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद की मार्गदर्शन में समाज को नयी व उन्नत दिशा–समाजवादी दिशा में बढ़ाने के लिए सभी वर्गों में योजनाबद्ध ढंग से सरकार के तौर पर और जनता के तरफ से भी प्रयास करती है। पार्टी, सरकार, सेना आदि क्षेत्रों के प्रशासनिकतंत्र में उभरने वाले तानाशाह, भ्रष्टाचार, भाईभतीजावाद, भेदभाव आदि जनविरोधी व प्रतिक्रियावादी रूझानों को समय पर रोकने के लिए न सिर्फ कानूनी तौर प्रयास करती है, बल्कि जनता–जनसंगठनों (ट्रेड यूनियनों, जनसंगठनों, जनवादी राजनीतिक पार्टियों, सांस्कृतिक संगठनों आदि) को प्रोत्साहित करती है, उन्हें जनवादी अधिकार दिलाती है।

एक कृषि क्षेत्र

नवजनवादी राज्य कृषि में शोषणमूलक उत्पादन–सम्बन्धों को खत्म करेगा व साम्राज्यवाद व बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कृषि की निर्भरता खत्म कर कृषि का वास्तविक विकास करेगा। अभी देश की कुल खेती योग्य 30 प्रतिशत से अधिक जमीन आबादी में 5 प्रतिशत होने वोले जमीन्दारों के कब्जे में है तथा कुल किसानों में से 65 प्रतिशत भूमिहीन गरीब किसान हैं जिनकी जोत एक हेक्टेयर से भी कम है। नव जनवादी राज्य जमीन्दारों व धर्म संस्थानों की सारी जमीन जब्त करेगा व 'जोतने वालों को जमीन' के आधार पर भूमिहीन व गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों के बीच अतिरिक्त जमीन का बंटवारा करेगा। यह भूमिहीन व गरीब किसानों के सरकारी, सहकारी व निजी कर्ज को रद्द कर देगा व किसानों लूटने वाली ऋण व्यापार संस्थानों को अपने नियंत्रण में लायेगा। यह सहकारी खेती को प्रोत्साहन देगा। जनता का श्रम व पूंजी ही इस सहकारिता के मुख्य संघटक होंगे जबकि इसमें कुंजीवत पहलू श्रम है। उपभोक्ता व ऋणदाता सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। यह पूंजीवादी कृषकों के बड़े फार्म, कारपोरेट सेक्टरर्स के फार्म, फार्म हाउस, प्लांटेशन व बागान आदि की सारी जमीन जब्त कर उन पर सामूहिक खेती कराये जाने को प्राथमिकता देगा।

सिंचाई व बिजली उत्पादन के लिए यह बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं की बजाय जमीन की बनावट के अनुसार छोटी–छोटी परियोजनाओं को यानी

चैकडैम एवं छोटे सिंचाई प्रोजेक्ट को प्रश्रय देगा। ताकि पर्यावरण का नुकसान व जनता को विस्थापन से बचा जा सके। किसी बड़ी परियोजना को अनिवार्यत: निर्माण करने की परिस्थिति सामने आने पर स्थानीय जनता की सहमति से व पर्यावरण का ख्याल रखकर ही बनाया जायेगा।

बाजार के उतार-चढ़ावों व कर्ज के बोझ से यह किसानों को आजाद करेगा। यह विश्व व्यापार संगठन से बाहर आयेगा व हर किसान विरोधी नीति को खारिज कर देगा। खेती में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शोषणकारी घुसपैठ को बंद किया जायेगा। खेती में नपुंसक संकर बीजों व बंजर बनाने वाले कृषि आगतों को प्रतिबंधित किया जायेगा व मिट्टी व जलवायु को ध्यान में रखकर देशी बीजों व खादों के प्रयोग एवं उसके अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जायेगा। यह कृषि में जरूरी चीजों में सहकारी समितियों व छोटे किसानों को सब्सिडी देगा। किसानों के फसलों को समर्थन मूल दी जाएगी। यह सबसे पहले खाद्यान के मामले में और पौष्टिकाहार के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनायेगा व सब्सिडी देकर सस्ते दामों पर खाद्यान के बंटवारे को सुनिश्चित करेगा। यह सरकारी योजनाओं में खेती पर खर्च को बढ़ायेगा व इसे प्राथमिकता देगा। इस तरह यह ''कृषि को बुनियाद के हिसाब से और उद्योग को आगे ले जाने वाले तत्व के हिसाब से लेने'' के सिद्धांत को और ''पांवों पर चलने'' की नीतियों की पूरी श्रृंखला को लागू करती है।

एक उद्योग क्षेत्र

नव जनवादी राज्य उद्योग-धंधों को साम्राज्यवादी नियंत्रण से दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त कर देगा व इसे आत्मनिर्भर होने लायक पुनर्निर्माण करेगा। यह साम्राज्यवादी व दलाल बड़े पूंजीपतियों की तमाम औद्योगिक व बैंकिंग पूंजी, सटोरियों की पूंजी, उनकी जमीन, भवन, बागान आदि, बड़े नौकरशाहों की अकूत संपत्ति व बैंकों में उनकी जमा राशि को जब्त करेगा। यह बड़े पूंजीपतियों, विदेशी पूंजीपतियों के तमाम फैक्टरियों, बैंकों, इन्सयूरेंश कंपनियों, अन्य वित्तीय निगमों, अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) विभागों आदि का सार्वजनीकरण कर देगा। यह बड़े उद्योगों में दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों और विदेशी पूंजीपतियों की पूंजी

के अस्तित्व को खत्म कर देगा। यह शासक वर्गों द्वारा किसी भी साम्राज्यवादी वित्तीय संस्था या देश से लिये गये कर्जों को रद्द कर देगा। यह आईएमएफ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन आदि साम्राज्यवादी संस्थानों से किये गये उन समझौतों को भी रद्द कर देगा जो हमारे उद्योग को निर्भरशील व परजीवी बनाते हैं। यह उदारीकरण, निजीकरण व भूमण्डलीकरण की साम्राज्यवादपरस्त नीतियों को खारिज कर देगा। यह आमतौर पर सरकारी पूंजी को मजबूत करते हुए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी के संचयन पर एक सीलिंग लगायेगा।

कृषि को आधार बनाकर ही उद्योगों की स्थापना व विकास होगा। यह श्रम आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा। ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच मौजूद असंतुलन को दूर करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित विकास कर, वहां पर उद्योग-धंधों का विकास कर शहरों में बढ़ रहे आबादी के दबाव को कम करेगा। ग्रामीण इलाकों से काम-धंधे के लिए शहरी क्षेत्रों में पलायन करने की स्थिति को धीरे-धीरे समाप्त करेगा।

आज संगठित क्षेत्र में मात्र 7 प्रतिशत लोग कार्यरत हैं। नवजनवादी राज्य उद्योगों में रोजगार को प्राथमिकता देगा, न कि मुनाफे को। यह 6 घंटे के कार्य-दिवस को लागू करेगा। यह मजदूरों के सन्दर्भ में कहीं भी ठेका प्रथा को समाप्त करेगा। यह महिला व पुरुष के लिये समान काम के लिये समान मजदूरी दर कायम करेगा। यह बाल मजदूरी को पूरी तरह खत्म कर देगा। मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्य-परिस्थिति मुहैया करायेगा।

यह काम के अधिकार को बुनियादी अधिकार के रूप में सुनिश्चित करेगा और बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

नव जनवादी राज्य तमाम सेज (विशेष आर्थिक जोन) को रद्द कर देगा।

नवगठित सरकार छोटे व मंझोले उद्योगों को संरक्षण देगी। देशीय पूंजीपति वर्ग के उद्योग-धंधों को सीमित व नियंत्रित करेगी तथा उद्योग, व्यापार वाणिज्य, कुटीर उद्योगों व हस्तकला के चहुमुखी विकास के लिए सहकारिता आंदोलन को भरपूर प्रोत्साहन दिया जायेगा।

राष्ट्रीयताओं के लिए आत्मनिर्णय अधिकार और एक स्वैच्छिक संघ का निर्माण

नव जनवादी राज्य बंदूक के बल पर किसी भी राष्ट्रीयता को भारतीय संघ में रखने की हिमायत नहीं करेगा जैसा कि अभी किया जा रहा है। आज की भारतीय विस्तारवादी सरकार ने कश्मीर को 5 लाख भारतीय फौज ने लौह बूटों से रौंद रखा है। मणिपुर, नागालैंड व असम समेत तमाम उत्तर-पूर्वी प्रांतों को वस्तुतः सैनिक राज्य में तब्दील कर दिया है। नवगठित राज्य तमाम राष्ट्रीयताओं के अलग होने के अधिकार सहित आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देकर तथा उन सभी को समान मर्यादा देकर समानता के आधार पर देश को एकताबद्ध करेगा। जो राष्ट्रीयता भारतीय संघ में रहना चाहेगी वह रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा का चलन आदि पर छोड़ तमाम आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक मामलों में स्वायत्त रहेगी। इस तरह जनवाद, आपसी सहमति व सहयोग पर आधारित होकर संघीय गणराज्यों के स्वैच्छिक संघ की स्थापना यह राज्य करेगा। यह राज्य सभी राष्ट्रीयताओं के भाषाओं को समान दर्जा देगा। यह बिना लिपि की भाषाओं के विकास में सहायता करेगा। राष्ट्र भाषा या सम्पर्क भाषा के नाम पर या किसी भी रूप में यह राज्य दूसरी राष्ट्रीयताओं पर किसी भी भाषा को नहीं थोपेगा। यह विभिन्न राष्ट्रीयताओं चहुमुखी विकास के लिए प्रयास करेगा। राष्ट्रीयताओं के बीच विभिन्न मुद्दों को आम सहमति से हल करेगा।

जाति उत्पीड़न और भेदभाव का उन्मूलन

नवजनवादी राज्य सामंती राजसत्ता को ध्वस्त करने द्वारा, 'जमीन जोतने वाले की' के आधार पर जमीन कर बँटवारा करके और गरीब किसानों तथा भूमिहीन किसानों (जिनका बड़ा हिस्सा दलित, आदिवासी तथा दूसरी उत्पीड़ित जातियाँ होंगी) के नेतृत्व वाली नयी सत्ता के सहारे समाज के बुनियाद में जड़ जमाये हुए जाति व्यवस्था के उन्मूलन की प्रक्रिया को शुरू करेगा। इसके लिए विशेष निर्माण व संघर्ष के तरीकों को अपनाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने द्वारा ब्राह्मणवादी विचारधारा, जातिगत भेदभाव और असमानताओं को, छुआछूत

तथा जातिप्रथा का सम्पूर्ण विनाश करने की ओर बढ़ेगा। यह जातीय भेदभाव करने वालों के साथ कड़ाई से निबटेगा। तब तक यह दलितों व सामाजिक रूप से अन्य उत्पीड़ित जातियों की उन्नति के लिए आरक्षण सहित विशेष सुविधाओं को सुनिश्चित करेगा।

महिलाओं को समान अधिकार

यह महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यह पुरुष-प्रभुत्व तथा पितृसत्ता को समाप्त करने के लिए संघर्ष करेगा। यह जमीन सहित सम्पति पर उनके समान अधिकार का भी गारंटी करेगा। यह सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, लिंगभेद आदि महिला विरोधी कुप्रथाओं को प्रतिबन्धित करेगा व इन कार्यों में लिप्त पाये गये दोषियों को सजा देगा। यह उपभोक्तावाद व महिलाओं को माल के रूप में इस्तेमाल करने वाली हर साम्राज्यवादी-पूंजीवादी प्रथा जैसे कि अश्लील साहित्य, नंगे विज्ञापन, सौन्दर्य प्रतियोगिता आदि को प्रतिबंधित करेगा। यह राज्य वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं का पुनर्वास करेगा और उन्हें सामाजिक मान्यता दिलवायेगा। यह महिलाओं को घरेलू कामकाज के जेल से मुक्त करायेगा व सामाजिक उत्पादन व अन्य गतिविधियों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले उत्पीड़न और भेदभाव को तेजी से उन्मूलन करने के लिए विशेष नीतियों का प्रोत्साहन करेगा। उनके लिए आरक्षण सहित विशेष सुविधाएं सुनिश्चित करेगा।

आदिवासियों के लिए स्वायत्तता

यह जल, जंगल व जमीन पर आदिवासियों-मूलवासियों के सामूहिक स्वामित्व को मान्यता देगा व उसका जन हित में इस्तेमाल हो, इसके लिए उन समुदायों को प्रोत्साहित करेगा। यह सभी आदिवासी समुदायों के सम्पूर्ण विकास के लिए उन्हें विभिन्न स्वायत्तताएं सुनिश्चित करेगा और तदनुसार विशेष नीतियां लागू करेगा।

एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण

धर्मनिरपेक्ष होने की संवैधानिक घोषणा के बावजूद भारतीय सत्ता 'हिन्दी,

हिन्दू, हिन्दुस्तान' की ब्राह्मणवादी और अंधराष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है। नव जनवादी राज्य के सांप्रदायिकरण और सभी किस्म की धर्मांधता के खिलाफ है। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार व धर्म-आधारित सामाजिक असमानताओं को समाप्त करेगा। यह उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये विशेष नीतियों को लागू करेगा। यह धार्मिक मामलों में राज्य की दखलंदाजी समाप्त करेगा। साथ ही, यह राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ध र्म के इस्तेमाल पर रोक लगायेगा। यह धर्म को मानने और न मानने की व्यक्तिगत आजादी की गारंटी करेगा।

एक नवजनवादी संस्कृति का निर्माण

भारतीय समाज हजारों सालों से जातियों में विभाजित ब्राह्मणवादी जातीय, सामाजिक अंतर, भेदभाव, रीति व अंध कुसंस्कारों पर आधारित एक समाज रहा है। ब्राह्मणवाद यहां के सामंतवाद की सांस्कृतिक रीढ़ है। नवगठित राज्य घृणास्पद जातिप्रथा, जहां जन्म के आधार पर सामाजिक तौर पर कोई ऊंच-नीच होता है, छुआछूत और भेदभाव को पूर्ण रूप से खत्म करने की ओर आगे बढ़ेगा। यह आदिवासियों के साथ किये जा रहे भेदभाव को खत्म करेगा।

यह देश के अंदर ब्राह्मणवादी हिंदू धर्मोन्मद विचाधारा का प्रभाव से धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति व्याप्त उत्पीड़न-भेदभाव का उन्मूलन करता है। समाज में एक वैज्ञानिक तथा तर्कसंगत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करेगा।

यह क्षरणशील सामंती, औपनिवेशिक व साम्राज्यवादी संस्कृति के स्थान पर जनवादी व प्रगतिशील संस्कृति को स्थापित करेगा। मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद की मार्गदर्शन में समाजवादी-साम्यवादी संस्कृति को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

स्वस्थ्य केन्द्र-राज्य संबंध

यह नया राज्य सभी स्तरों पर जनता के जनवादी संविधान के अनुसार और उसके आधार पर क्रान्तिकारी जन समितियों और जन सरकारी परिषदों के द्वारा जनता की राजनीतिक सत्ता को स्थापित करेगा। यह प्रतिनिधि-सभाओं को

गप्पबाजी का अड्डा व दिखावे का दांत नहीं, सही कामकाजी सत्ता केन्द्र के रूप में विकसित करेगा। यह भारत की राजनीति, शासन व संस्कृति में विद्यमान सभी औपनिवेशिक ढांचों, कानूनों व प्रभावों को खत्म कर देगा।

सभी लोगों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी (बोलने, लिखने व प्रेस की आजादी) सहित इकट्ठा होने, संगठित होने और हड़ताल व प्रदर्शन करने के अधिकारों जैसे जनवादी अधिकारों को यह राज्य सुनिश्चित करेगा। यह राजसत्ता द्वारा हर दिन के शासन कार्यों के संचालन पर जनता के हिस्सा लेने और राजसत्ता पर जनता के नियंत्रण के अधिकार को सुनिश्चित करेगा तथा इस अधिकार को घटाने की हर कोशिश को रोकेगा।

यह केन्द्र व राज्यों के बीच मौजूद सभी असमान रिश्तों को खत्म करेगा व स्वस्थ्य रिश्तों को पुनर्निर्माण करेगा। यह केन्द्र व राज्यों के बीच व्यवहार के क्रम में उभरने वाले किसी भी समस्या को संघ के मौलिक कार्यक्रम को ध्यान में रखकर जनवादी तरीके अपनाते हुए, आपसी सहयोग व सलाह-मशविरा के जरिए हल करेगा। राज्यों को रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा का चलन आदि पर छोड़ आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक मामलों में स्वायत्त बनाएगा व केन्द्र व राज्यों के बीच मौजूदा आधिपत्यवादी के रिश्ते को खत्म करेगा।

यह पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयासों के जरिये क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करने की ओर आगे बढ़ेगा। यह प्रांतों के बीच नदी जल बंटवारा, सीमा विवाद जैसे मुद्दों को आम सहमति से हल करेगा।

एक कल्याणकारी राज्य

यह रोजगार, शिक्षा व चिकित्सा के अधिकारों को बुनियादी अधिकार के रूप में सुनिश्चित करेगा व बेरोजगारी को खत्म करने की ओर आगे बढ़ेगा। यह अभिजात्य केन्द्रित व देशी-विदेशी बड़ी पूंजी की सेवा करने के उद्देश्य से बनायी गयी शिक्षा प्रणाली को खत्म कर एक मजदूर, किसान आदि सभी श्रमजीवी जनता के लिए सर्वसुलभ, देश के हितों व विशेषताओं को ध्यान में रखने वाली जनवादी व वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली को विकसित करेगा जो शिक्षा को उत्पादन से जोड़ेगा। यह राज्य बेकारी भत्ता और सामाजिक बीमा लागू

करेगा तथा लोगों के लिए बेहतर जीवन-यापन की स्थिति सुनिश्चित करेगा।

यह शारीरिक रूप से विकलांगों, मानसिक रूप से अक्षम व विकलांगों, बुजुर्गों व अनाथों तथा अपंगता से ग्रस्त अन्यान्य लोगों को उपयुक्त आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा तथा एक स्वस्थ्य सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण मुहैय्या करायेगा।

यह सभी लोगों के लिए खासकर मजदूरों, किसानों व अन्यान्य मेहनतकश जनता के लिए उत्तम स्वास्थ्य व मुफ्त चिकित्सा की सुनिश्चितता प्रदान करने वाली एक जनमुखी चिकित्सा प्रणाली को लागू करेगा। देश का समूचा स्वास्थ्य क्षेत्र जन सरकार के अधीन रहेगा। चिकित्सकों का अस्पताल में जाना अनिवार्य बनाया जायेगा।

यह पेयजल, बिजली व यातायात, संचार व अन्य जनोपयोगी क्षेत्र में मुनाफे पर आधारित निजी व्यवस्था खत्म करेगा व तमाम क्षेत्रों को सरकारी दायरे में लायेगा। यह मानसिक व शारीरिक श्रम के बीच दूरी को क्रमशः घटाने का प्रयास करेगा। यह तमाम भारी करों को समाप्त करेगा और मौजूदा कर-प्रणाली को रद्द कर देगा और एक सरल व प्रगतिशील कर-प्रणाली लागू करेगा।

जन न्याय प्रणाली

यह एक जनपक्षीय, प्रगतिशील और जनवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी को सुधारने के लिए यथोचित न्याय सुनिश्चित करने वाली न्याय प्रणाली व न्याय व्यवस्था को लागू करेगा। इस दिशा में यह आज की मंहगी न्याय प्रणाली को हटाकर सस्ता व जनसुलभ न्याय प्रणाली को बनायेगा।

पर्यावरण व विस्थापन

मुनाफे की होड़ में दुनिया भर के पूंजीपतियों, खासकर अमरीका व बाकी साम्राज्यवादी देशों के पूंजीपतियों ने पर्यावरण का अकथनीय नुकसान किया है; इतना कि पृथ्वी के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। यह नवजनवादी राज्य दुनिया के अन्य समान विचार वाले देशों के साथ मिलकर साम्राज्यवादी देशों पर प्रदूषण घटाने व इसके लिए लागत देने हेतु दबाव बनायेगा। यह बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं, जंगल की कटाई, अन्य पर्यावरण विरोधी प्रोजेक्टों को

हतोत्साहित करेगा व जरूरत पड़ने से उन्हें प्रतिबंधित करेगा।

भारत में विभिन्न परियोजनाओं में 1947 से अब तक 6 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं जिनमें अधिकांश आदिवासी हैं। यह राज्य बिना जनमत संग्रह किये और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए किसी भी स्थान पर विकास प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करेगा। जन हित में अपनाई जाने वाली किसी भी प्रोजेक्ट से हुए विस्थापन की स्थिति में सम्पूर्ण पुनर्वास व रोजगार की गारंटी के बाद ही प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा।

अंतरराष्ट्रीय तौर पर एक सौहार्द संबंध व सम्प्रभुता वाली देश

यह साम्राज्यवाद देशों के साथ मौजूदा प्रतिक्रियावादी और जनविरोधी सरकार द्वारा किये गये सभी असमान, राष्ट्रविरोधी, देश की संप्रभुता को चोट पहुंचाने वाली संधियों को रद्द करेगी। यह राज्य देश की सुरक्षा के लिए जनता को हथियारबंद करेगा और देश की रक्षा में जनता की भूमिका बढ़ाएगा।

वर्तमान शासकों के विस्तारवादी मंसूबों के विपरीत यह राज्य अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बंध कायम करेगा। यह पड़ोसी देशों के साथ सीमा, पानी और दूसरे विवादों को शान्तिपूर्ण व न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाने का भरपूर प्रयास करेगा। यह राज्य पड़ोसी देशों के साथ कभी भी विस्तारवादी व्यवहार नहीं करेगा।

आज की दुनिया में विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले देशों के साथ सम्बन्धों में यह राज्य निम्न पांच सिद्धान्तों का पालन करेगा – क्षेत्रीय अखण्डता व सम्प्रभुता का परस्पर सम्मान, परस्पर अनाक्रमण, एक–दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, बराबरी एवं परस्पर हित तथा शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व।

संक्षेप में यही है नव जनवादी सत्ता द्वारा पेश मुख्य बुनियादी वैकल्पिक कार्यक्रम की रूपरेखा।

प्रिय जनता और मित्रों!

जन पक्षीय और जनता तथा देश के लिए मुक्ति दिलाने वाली वैकल्पिक कार्यक्रमों के साथ जनता की जनवादी सत्ता स्थापित करने के लक्ष्य से हमारी पार्टी के नेतृत्व में नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष से लेकर देशभर में,

विशेषकर आज दंडकारण्य, बिहार-झारखण्ड, पूर्वीबिहार-पूर्वोत्तर झारखण्ड, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्रप्रदेश, आंध्र-ओड़िशा सीमा इलाका (एओबी), तेलंगाना, मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ (एमएमसी), पश्चिमीघाटी (कर्नाटक-तमिलनाडु-केरलम सीमा) की ट्राइजंक्शन आदि इलाकों में साम्राज्यवाद-विरोधी और सामंतवाद-विरोधी हथियारबन्द संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष का लक्ष्य नव जनवादी क्रान्ति पूरी कर नव जनवादी राज्य बनाना है ताकि अपने देश को मुक्त, आत्मनिर्भर व समृद्ध बनाया जा सके। इस आन्दोलन से करोड़ों भूमिहीन व गरीब किसान, खेतिहर मजदूर और मध्यम किसान कुछ जगहों पर धनी किसान शामिल हो रहे हैं; क्रांतिकारी जनसंगठनों और क्रांतिकारी जन कमेटियों में संगठित हो रहे हैं व अपने सपनों का भारत बनाने के लिए लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं।

शासक वर्गों की सरकार इसे किसी भी हालत में कुचल देना चाहती है। विगत यूपीए 1, 2 सरकारें की तरह ही देश का प्रधानमंत्री मोदी जो स्वयं अमरीका का विश्वस्त एजेंट है और उसके सिपहसलारों ने जो अमरीका और अन्य साम्राज्यवादी ताकतों के भरोसेमंद दलाल व सेवक हैं, भी घोषित किया कि हमारी पार्टी - भाकपा (माओवादी) को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमारी पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन को पूरी तरह सफाया करने के लक्ष्य से यूपीए सरकार द्वारा जारी ''जनता पर युद्ध'' के तौर पर बहुचर्चित चौतरफा हमला - ''ऑपरेशन ग्रीनहंट'' को ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादी भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और तेज की थी। वह मई 2017 से उसकी जगह और क्रूर फासीवादी ''समाधान'' रणनीति को सामने लायी। कश्मीर और उत्तर-पूर्व इलाकों और क्रांतिकारी इलाकों में प्रतिक्रांतिकारी सलवा जुडुम (सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में बताया कि जनता के बीच गृहयुद्ध पैदा करने वाली सलवा जुडुम जैसे अभियानों को राज्य समर्थन देना ठीक नहीं है और इसे रोकना चाहिए), सेंद्रा जैसे अभियानों में मिली अनुभवों को ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादी मोदी-शाह-भागवत गुट ने पूरी देश में विस्थारित किया। राज्य प्रत्यक्ष रूप से अपने सशस्त्र बलों को तैनात कर चलाये जाने ऑपरेशनों और अभियानों के साथ-साथ गैरराज्यीय तत्वों (non-state actors) को प्रोत्साहन देकर क्रांतिकारी आंदोलन पर हमला करना दिन-ब-दिन बढ़ता गया। दरअसल, यह आन्दोलन जल-जंगल-जमीन- इज्जत-अधिकार के

लिए व तमाम आर्थिक-राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए जारी जनता का आन्दोलन है। इसे ध्वस्त करने हेतु अत्याधुनिक हथियारों से लैस पांच-छह लाख अर्द्धसैनिक बलों को तैनात कर और प्रशिक्षण की आड़ में सेना की तैनाती की तैयारियां करते हुए 12 राज्यों के देहाती क्षेत्रों को पुलिस-मिलिटरी की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और इस तरह जनता के खिलाफ एक अन्यायपूर्ण युद्ध चलाया जा रहा है। गिरफ्तारी, मानसिक व शारीरिक यातनाएं, हत्या, गुप्त हत्या, लापता, महिलाओं का बलात्कार-हत्या इत्यादि अमानवीय अत्याचार लगातार जारी हैं। संविधान, कानूनों और कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन कर झूठी मुठभेड़ों, दर्जनों हत्याकाण्डों के जरिए सफेद आतंक पैदा करते हुए न्यूनतम जनवादी अधिकारों को भी आज पुलिसिया बूटों तले रौंदा जा रहा है। मोदी की शासन में क्रांतिकारी इलाकों में लगभग 420 क्रांतिकारियों और 360 आम जनता को हत्या की गयी है। एक सौ से अधिक आदिवासी युवतियों पर अत्याचार कर, उनमें से कइयों को हत्या की गयी है। घरों-गांवों में आगजनी, 'उपा' जैसे क्रूर कानून लगाकर हजारों लोगों को जेलों में ठूंस देना, पत्रकारों, लेखकों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिला व आदिवासी जनसंगठनों के कार्यकर्ताओं को धमकियां देना पुलिस की दिनचर्या बन गयी है। आंदोलन के इलाकों और इससे बाहर वाली मैदान और शहरी इलाकों में भी खुले व कानूनी जनांदोलनों पर भी तीव्र दमन आम बात बन गयी है। दूसरा तरफ विभिन्न उत्पीड़ित वर्गों और सामाजिक तबकों द्वारा जारी जनांदोलनों और जनवादी आंदोलनों पर भी केन्द्र-राज्य सरकारें तीव्र दमन लागू कर रही हैं। कश्मीर और उत्तरपूर्व जैसे उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं द्वारा दशकों साल से अलग होने के अधिकार सहित राष्ट्रीयताओं के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए जारी राष्ट्रीय-मुक्ति संघर्षों को केन्द्र सरकार ने भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर लौहे के पैरों से कुचल रही है। सशस्त्र बलों के विशेष अधिकार कानून को लागू कर देश को राष्ट्रीयताओं के लिए बंदीखाना के रूप में तब्दील कर दिया। कश्मीर में 370 व 35ए धाराओं को कुचल दी है। इस तरह देश में संसदीय जनवाद के नाम पर पूरी तरह दलाल नौकरशाह और बड़े सामंतियों का तानाशाही अमल हो रही है और अघोषित आपातकाल की स्थिति जारी है। ऐसी स्थिति में, भारत की जनता इसी देश के सशस्त्र बलों से युद्ध लड़ने को मजबूर है।

इन धोखेबाजी और कपटतापूर्ण चुनावों का मुख्य उद्देश्य इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि किस शासकीय गुट सत्ता में आना है और किस शासकीय गुट और पांच सालों तक साम्राज्यवादियों और देश के शोषक वर्गों के हित पूरा करने के लिए व्यापक जनसमुदायों पर अपनी क्रूर शासन जारी रखना है। इस झूठी संसदीय जनवाद में जो लोग साम्राज्यवादी ग्लोबल कार्पोरेटों के लिए हमारा देश की अर्थव्यवस्था की दरवाजे पूरी तरह खोलने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं; जो लोग कानून सभाओं, केंद्र व राज्य सरकारों, सरकारी सशस्त्र बलों, न्यायालयों और प्रसारण साधनों के जरिए एलपीजी नीतियों को संचालित करने में दक्ष हैं; जो लोग इस लुटेरी व्यवस्था के प्रति जनता के अंदर बढ़ती असंतुष्ट और आक्रोश को तथा जनवादी, क्रांतिकारी, राष्ट्रीय-मुक्ति संघर्षों को क्रूरता से कुचलने में सक्षम हैं तथा जो लोग इस सड़ीगली व्यवस्था के विकल्प के रूप में माओवादी पार्टी के नेतृत्व में अंकुरित होने वाली जनता की सच्ची क्रांतिकारी सत्ता को उखाड़ने के लिए 'ग्रीनहंट', 'समाधान' जैसे रणनीतिक हमलों को अंजाम देने में दक्ष हैं उन्हीं लोग चुनावों में जीत हासिल कर सकते हैं। जो करोड़पतियों जिन्हें धन-अंग बल होने वाली देश-विदेशी कार्पोरेटों के समर्थनप्राप्त है, जो लोग फासीवाद - यानी धर्मान्माद, जाति-उन्माद और प्रांतीयउन्माद को भड़काकर जनता के अंदर फूट डालने-राज करने समक्ष हैं, मोदी, अमित शाह जैसे लोग जो हजारों लोगों को हत्या करने में समक्ष हैं, जो लोग धन-दारू के साथ वोटरों को खरीद सकते हैं, रिगिंग कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं लोग चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी कोई आम जनता को उस मौका नहीं मिलेगी। इसमें जीतने वाले सांसदों (एमपी) और विधायकों से जनता के लिए जवाबदेही होने की कोई जरूरत नहीं है। पांच सालों तक निरंकुश शासन जारी रखने की अधिकार उन्हें मिलती है।

लेकिन इसका पूरा विपरीत है, हमारे द्वारा प्रस्तावित सच्ची स्वतंत्र, प्रगतिशील, प्रभावशाली, स्वावलंबी, शोषणमुक्त भारतीय जनता के संघीय जनतांत्रिक गणतंत्र की आज की भ्रूणरूप में होने वाली क्रांतिकारी जन कमेटियां (आरपीसी)। नवजनवादी राज्य कट्टर प्रतिक्रियावादियों को छोड़कर, 18 वर्ष होने वाले सभी नागरिकों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी स्तरों में चुनने की अधिकार, चुने गए जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का (Recall) अधिकार देगा। सभी जनता के लिए जनवादी अधिकार सुनिश्चित करेगा। देश

के संघर्षरत किसानों, मजदूरों, मध्यम वर्ग, छात्र–युवा, बुद्धिजीवियों, जनवादीप्रेमियों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि जनता ने साम्राज्यवादियों के बल पर भारतीय शासक वर्गों/केन्द्र–राज्य सरकारों द्वारा जारी अन्यायपूर्ण युद्ध का न केवल न्यायपूर्ण युद्ध के जरिए मुकाबला कर रही है बल्कि बतौर इस वैकल्पिक व्यवस्था–नव जनवादी राजसत्ता के भ्रूण के रूप में क्रान्तिकारी जन कमेटियों को बनाना शुरू कर दिया है। कुछ जगहों पर जिला स्तर तक की क्रान्तिकारी जन कमेटियां संगठित कर ली गयी हैं। भविष्य में विकासक्रम में यही नवजनवादी सरकार ही भारत की क्रान्तिकारी संघीय जनवादी सरकार के रूप में विकसित होगी। यह चार वर्गों – मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग और देशीय बुर्जुआ, उत्पीड़ित सामाजिक तबकों तथा उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के संयुक्त मोर्चे की सरकार है। हालांकि शासक वर्गों की सरकार इसे कुचल देने हेतु जी–जान से लगी है, फिर भी जनता की सरकार ने अपने नवजनवादी नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया है।

तमाम मजदूरों, किसानों, मध्यमवर्ग, देशीय पूंजीपतियों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं, देशभक्त, प्रगतिशील व जनवादी व्यक्तियों व समूहों का हम आह्वान करते हैं कि वे इस नवजनवादी राज्य के निर्माण में अपना योगदान दें, इस न्यायपूर्ण युद्ध में शामिल हों, वर्तमान शोषणकारी, साम्राज्यवादपरस्त राजसत्ता को नकार कर इनकी प्रतिनिधि– सभाओं (संसद, विधानसभाओं और पंचायतों) के लिये होने वाले चुनावों का बहिष्कार करें। आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करें।

क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ,

केन्द्रीय कमिटी

5 जनवरी 2019 **भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)**

~ ★ ~